AD EDUXIAN JOURNAL
A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed Online International Journal
Google Scholar Indexing PIF: 1.048(I2OR) & 3.125 (IIFS)
Vol (3), Issue (1), January-March 2026 ISSN: 3048-7951

उच्च शिक्षा में सुधार

गौतम[1]

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18948405
Review: 04/02/2026 Acceptance: 04/02/2026 Publication: 10/03/2026

सारांश:

हमारे देश में उच्च शिक्षा से जुड़े सभी लोगों ने उच्च शिक्षा की दशा को देख चिंता को व्यक्त किया है। हमारे देश में उच्च शिक्षा प्रणाली संस्थागत परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। यह बहुत लंबे समय से वित्तीय संसाधन, कक्षा, शिक्षक और कॉलेज/विश्वविद्यालय के छात्र जैसे विवादों में उलझा हुआ है। यह "बात और चाक" आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। जब से राष्ट्र ने आर्थिक विकास और सामाजिक विभाग को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा के मूल्य को मान्यता दी है, तब से सुधार के लिए दबाव बढ़ रहा है। राधा कृष्णन आयोग के समय से लेकर रस्तोगी समिति तक उच्च शिक्षा में सुधार का प्रयास किया गया। अतीत का विश्लेषण और भविष्य के लिए आवश्यकताओं का अनुमान समय की मांग है।

बीज शब्द: उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय, सुधार।

प्रस्तावना:

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने डॉ. वाई राजन (1998) के साथ भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की क्षमता पर चर्चा करते हुए सुझाव दिया कि लगभग पांच चिन्हित क्षेत्रों में केंद्रित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और इसके परिणामस्वरूप, वे राष्ट्र के परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएंगे, "इंडिया 2020: ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम"। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने स्पष्टता के साथ भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए एक संसाधन के रूप में हमारे अरबों लोगों का उल्लेख किया है।

नई सहस्राब्दी के लिए उनकी दृष्टि में यह भारतीय लोग राष्ट्र की संपत्ति हैं। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि आर्थिक विकास सिद्धांतों ने आर्थिक विकास कुंजी के रूप में मानव पूंजी की भूमिका पर जोर दिया है (गौतम और त्रिपाठी-2004) । मानव विकास 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट, "राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति उसके लोग हैं" शब्दों के साथ शुरू हुई। इस संदर्भ में पिछले चार दशकों में विभिन्न देशों का अनुभव हमारे लिए काफी प्रासंगिक है। यह देखा गया है कि केवल भौतिक और पूंजीगत संसाधन ही किसी देश को विकसित करने के लिए पर्याप्त इनपुट नहीं हैं (सुधा राव-2002)। भौतिक और पूंजीगत संसाधनों की प्रभावशीलता के बारे में कुछ तिमाहियों में गंभीर संदेह भी उठाए गए हैं और तर्क दिया गया है कि भौतिक लाभ और समृद्धि का अधिग्रहण, आर्थिक विकास का लक्ष्य, धन के वितरण में स्पष्ट असमानताओं और विकृतियों का कारण बन सकता है (आलम और झोन- 2000 इसलिए, विकसित होने का सपना देख रहे राष्ट्र को अपने मानव संसाधन का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए और इसे राष्ट्रीय संपत्ति में परिवर्तित करना चाहिए।

मानव संसाधन के महत्व और इसे विकसित करने में शिक्षा की भूमिका को मानव सभ्यताओं की शुरुआत से ही अच्छी तरह से पहचाना गया है। इसके अलावा, उन्नत औद्योगिक देशों/समाजों की अर्थव्यवस्थाएं एक अभूतपूर्व सीमा तक, वैज्ञानिक

[1] गौतम, स्नातकोत्तर शिक्षक, दीप नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय,पूरणटांड,वैशाली।

अनुसंधान के परिणाम पर, कुशल और जिम्मेदार जनशक्ति की आपूर्ति पर और शिक्षा प्रणाली की दक्षता पर क्रमिक रूप से निर्भर पाई गई, (हालसे एवं अन्य, 961)। इसलिए, मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण इनपुट माना जाता है। इसके अलावा, वर्तमान समाज को एक ज्ञान समाज के रूप में विकसित किया जा रहा है। निश्चय ही शिक्षा के बिना ऐसा विकास असंभव है। विश्व बैंक और यूनेस्को द्वारा वर्ष 2000 में नियुक्त उच्च शिक्षा और समाज पर टास्क फोर्स ने सुझाव दिया कि अधिक और बेहतर शिक्षा के बिना, विकासशील देशों को वैश्विक-ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था से लाभ उठाना मुश्किल होगा। संक्षेप में, शिक्षा लोगों को उनके सशक्तिकरण के लिए ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान करने का एक साधन है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों के बीच, उच्च शिक्षा का राष्ट्र के विकास पर व्यापक और प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। उच्च शिक्षा व्यक्ति को व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और क्षमता प्रदान करती है, जो अंततः राष्ट्र के विकास में योगदान करती है। विश्व बैंक का एक हालिया अध्ययन भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

भारत में विश्व में सबसे अधिक उच्च शिक्षण संस्थान हैं। 2021-22 के यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार, 455 राज्य विश्वविद्यालयों में 39931 कॉलेज, 55 केंद्रीय विश्वविद्यालय 123 डीम्ड विश्वविद्यालय, 74 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान थे। 1947 में भारत में 50 से भी कम विश्वविद्यालय थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण यानि 1990 के दशक के बाद से हर स्तर पर इन संस्थानों में नामांकन के साथ-साथ देश में शैक्षणिक संस्थानों का विस्तार हो रहा है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उच्च शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यह युवा लोगों को प्रासंगिक कौशल प्रदान करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता है जो राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक हैं। भारत में उच्च शिक्षा की प्रकृति काफी जटिल है जिसमें विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं-केंद्रीय, विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, एकात्मक और संबद्ध विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और अनुसंधान संस्थान, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, मुक्त विश्वविद्यालय के अतिरिक्त महिलाओं, अल्पसंख्यक संस्थानों आदि जैसे कुछ समूहों के लिए अलग से शिक्षण संस्थाएं। मूल रूप से यह एक त्रिस्तरीय संरचना है। प्रथम श्रेणी में एम्स, आईआईटी आदि जैसे अति विशिष्ट संस्थान हैं। दूसरे स्तर में राज्य, केंद्र और अन्य विश्वविद्यालय हैं। तीसरे स्तर में विश्वविद्यालय, संस्थान शामिल हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना है। हाल ही में यू.जी.सी. ने 24 डीम्ड विश्वविद्यालयों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। कुछ विश्वविद्यालय तो केवल डिग्री प्राप्त करने की दुकान बन गए हैं। यूजीसी समय-समय पर देश भर के विश्वविद्यालयों की निगरानी करता रहा है। सीएमजे विश्वविद्यालय, मेघालय द्वारा जारी डिग्री को यूजीसी द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है। हाल ही में यूजीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र या राज्य से बाहर मुक्त विश्वविद्यालयों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश में उच्च शिक्षा में सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

सुधारों की आवश्यकता क्यों है:-

मांग और आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिये-

आकांक्षा और उपलब्धता के बीच एक अंतर है। समाज ने कई बार चिंता व्यक्त की है कि उच्च शिक्षा रोजगार योग्य प्रतिभाओं का उत्पादन नहीं कर रही है। उच्च शिक्षा में मांग और आपूर्ति का अंतर काफी बड़ा है। भारत एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। नई आवश्यकतानुसार नए ज्ञान का विस्तार हुआ है जिसके कारण देश में पारंपरिक, दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन

कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाले निजी और विदेशी शिक्षा प्रदाताओं का प्रवेश हुआ है। उच्च शिक्षा की मांग में इस वृद्धि ने नई वितरण विधियों और नए प्रकार के कार्यक्रमों का निर्माण किया है।

उच्च शिक्षा उण निर्दोष जनता के कर का पैसा लगा है जिसके बदले में उसे सिर्फ डिग्रियाँ दी जा रही हैं।उच्छत्तर मध्यमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षण संस्थान संक्रमण की संकरम,अन काल से गुजर रही हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं में गहरी आस्था के कारण कई बार छात्र धोखे का शिकार होते हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं में नामांकन वैसे छात्रों का हो रहा जिनके शैक्षणिक दृष्टिकोण और शैक्षणिक योग्यता के बीच काफी अंतर है। इसी तरह, उच्च शिक्षा के लिए नियोजित बड़े शिक्षक के शिक्षण दृष्टिकोण और शिक्षण योग्यता के बीच अंतर है। वे विभिन्न विधाओं में छात्रों और शिक्षक की योग्यता में असंतुलन पैदा करता है। बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थिति और भी चिंताजनक है। राज्य के विश्वविद्यालयों में कई कॉलेज ऐसे हैं, जिनमें केवल एक शिक्षक है। ऐसी स्थिति में भयावहता की कल्पना कोई भी कर सकता है।

निम्न गुणवत्तायुक्त शिक्षण-

शिक्षा की किसी भी प्रणाली में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। जो निर्भर करती है उच्च शिक्षा और अनुसंधान में प्रवेश प्रक्रिया पर। शिक्षक द्वारा अपेक्षित, विकसित और अभ्यास की गई शिक्षण दक्षताओं के बीच व्यापक बोधगम्य अंतराल पाया गया हैं। शिक्षण और अंततः अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से इनपुट केंद्रित और क्रेडेंशियल-केंद्रित दृष्टिकोण से शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में बदलाव किया गया है। उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए भी शिक्षकों के पर्याप्त केंद्र की उपलब्धता और उनकी क्षमता और कौशल के विकास के लिए उचित व्यवस्था करना आवश्यक है। प्रौद्योगिकी संचालित उच्च शिक्षा में, शिक्षक की भूमिका रूपांतरित हो जाती है। कुशल और योग्य शिक्षकों की देशव्यापी कमी को देखते हुए, 2013 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन में शिक्षक और शिक्षण पर एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की थी।

अनुसंधान क्षमता और नवाचारोंको प्रोत्साहन का अभाव-

भारत में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार की घोर कमी है। भारत में उच्च शिक्षा की प्राथमिकता अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए कभी नहीं रही है। हाल ही में पटना विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह में, भारत के प्रधान मंत्री ने विश्वविद्यालय को अनुसंधान और नवाचारों पर जोर देने का सुझाव दिया। एक सिविल सेवक और सीईओ का उत्पादन समाज की मदद करने वाला नहीं है। स्वदेशी संदर्भों का उपयोग करते हुए अनुसंधान और नवाचार समाज को और अधिक आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। गो ऑफ इंडिया ने सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम शुरू की है, जहां कॉरपोरेट को अपने लाभ का एक निश्चित प्रतिशत अनुसंधान और नवाचार पर खर्च करना है, ने अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप इंडिया योजना भी कहा जा रहा है। यूजीसी ने अनुसंधान एवं फेलोशिप की संख्या में कई गुना वृद्धि की है। ये सभी उपाय सरकार के ईमानदार प्रयासों को दर्शाते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में विशेष जोर दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा में भारत के राज्यों, देशों के बीच छात्रों की गतिशीलता में तेजी से वृद्धि हुई, उच्च

शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण और विश्वविद्यालयों के बीच सर्वश्रेष्ठ छात्रों, शोधकर्ताओं और संकायों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रहा है।

असमान विकास, वितरण और अवसर-

भारत में उच्च शिक्षा में तीन ई (E) प्रमुख चुनौतियाँ दृष्टिगत है- इक्विटी (Equity), विस्तार (Expansion) और उत्कृष्टता (Excellence)। पिरामिडिक व्यवस्था में नीचे के लोग शिक्षा के लाभों से बाहर हैं। हमारे 29 राज्यों में से आधे से अधिक संस्थानों में क्षेत्रीय फैलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में भी काफी भिन्नताएं हैं। भारत सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों की उत्कृष्टता का प्रदर्शन हेतु नैक का मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है।

भारत में ग्रामीण क्षेत्र, महिला और अलग-अलग धार्मिक समूह उच्च शिक्षा तक पहुंच को अवरुद्ध कर रहा है। उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है जिस कारण समाज के अंदर असमान सामाजिक आर्थिक विकास, विभिन्न श्रेणियों और क्षेत्रों के बीच खाई पैदा कर रही है।

भारत उतरोत्तर उच्चतर संस्थानों का विस्तार हो रहा है, जिसमे ज्यातर निजी तौर पर वित्त पोषित हैं। जो उच्च शिक्षा तक सभी की समान रूप से पहुँच को प्रभावित करता है। बदलते हुए परिवेश में यह एक प्रकार का जोखिम भरा कदम हो सकता है। विविध चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने, बहुत व्यापक और महत्वाकांक्षी योजना-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) अक्टूबर 2013 को नए रूप में लाया गया। 1857 में केवल तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ शुरू हुई भारतीय आधुनिक शिक्षा पद्धति दुनिया के सबसे लंबे शैक्षिक नेटवर्क में से एक के रूप में विकसित हुआ है।

आज भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली चौराहे पर खड़ी है। उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की हमारी सारी खोज विरोधाभासी प्रतीत हो रहीं हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत को केवल एक ही कार्य करना है, जो ऊपर सुझाए गए सुधारों पर फिर से विचार करना है, तदनुसार वर्तमान वास्तविकताओं, आशाओं और प्रेरणाओं के अनुसार समाज अधिक महत्वपूर्ण है, उनका प्रभावी कार्यान्वयन। और तभी हम भारतीय उच्च शिक्षा को वांछित उत्कृष्टता प्राप्त करने के बारे में सोच सकते हैं।

संदर्भ:

- अब्दुल कलाम ए.पी.जे.,और राजन,वाई.एस. (1988). भारत 2020: ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, पैंगविन बूक इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
- अग्रवाल पासवान (2009). इंडियन हाईयर एडुकेशन, इन्विसिनिंग द फ्युचर।
- आलम अनवर और जॉन ए.जी. (2004). एडुकेशन: एन इंडेक्स ऑफ ह्यूमन डेव्लपमेंट, यूनिवर्सिटी न्यूज, वॉल्यूम-42, सं.46, पृष्ट-25-29.
- अलटबेक, फिलिप जी. (2005). जी.इ.इन इंडिया द हिन्दू, अप्रैल-12.

- बेरलिया, शुश्मा (2004). द हाईयर एडुकेशन समिट-रोडमैप फॉर द फ्युचर, थीम पर्सेंटेशन, ग्लोबल कोन्फ्रेंस, एफ आइ सी सी एस, नई दिल्ली।
- गौतम एन.सी. और ट्रिमपैथी एस.के. (2004). इंगेजमेंटऑफ यूनिवर्सिटी विथ द सोसाइटी: ए मॉडल फॉर प्रोमोटिंग नॉन-फॉर्मल एडुकेशन थ्रो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी न्यूज वॉल्यूम-42, सं.46,पृष्ट-30-32.
- कुमार आशुतोष, शिक्षा आयोग की चुनौतियाँ, विशाल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- श्रीनिवास सुधा राव (2002). इक्यूलिटी इन हाईयर एडुकेशन, द इम्पैक्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन पौलिसी इन इंडिया, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ,वाशिंगटन डी.सी. पृष्ट- 41-46.
- स्टेला, एंथोनी(2001). क्वालिटी एस्सेस्मेंट इन इंडियन हाईयर एडुकेशन इश्यू ऑफ इम्पैक्ट एंड फ्यूचर परेस्पेक्टिव, एलाइएड पब्लिकेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।
- थोराट एस. (2013). अन्लर्निंग अनडेमोक्रेटिक वैल्यू, दि हिन्दू,दिस्मबर 26, 2013
- यू.जी.सी. (2012). हाईयर एडुकेशन इन इंडिया, टूवेल्थ फाइव ईयर प्लान (2012-17) एण्ड बियोंड.
- यू.जी.सी. एनुयल रिपोर्ट